

कई और दवाओं के दामों पर लगोगी लगाम

■ वरिष्ठ संवाददाता, नई दिल्ली
सरकार प्राइस कंट्रोल के दायरे में
कई और दवाओं को शामिल करने
पर विचार कर रही है। अभी 348
बल्क ड्रग्स और इनके संयोग
से बनने वाली 654
दवाएं इसके दायरे में
शामिल हैं। सरकार के
इरादे से दवा कंपनियों
में खासी बेचैनी है।
वह इससे पहले भी 348
दवाओं को मूल्य नियंत्रण
के दायरे में लाने के खिलाफ थीं।
इसी कारण कई दवा कंपनियों ने
प्राइस रिवीजन के लिए नेशनल
फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी में
अपील दायर की थी।
सूत्रों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल
के दायरे में शामिल की जाने वाली



नई दवाओं में कई एंटीबायोटिक्स
के अलावा कैंसर की दवाएं भी
शामिल हैं। नई दवाओं के मामलों
पर विचार करने के लिए एक पैनल
का गठन किया गया है। गौरतलब
है कि जब सरकार ने प्राइस
कंट्रोल के दायरे में 74
की जगह 348 दवाओं
को शामिल करने का
फैसला किया था तो
दवा कंपनियों ने उसका
काफी विरोध किया था।
दूसरी ओर, तब कई स्वयंसेवी
संगठन और पॉलिटिशन दवाओं के
रेट तट करने के फॉर्म्युले से नाखुश
थे। सरकार ने नई दवाओं के रेट तय
करने का आधार बाजार में उपलब्ध
दवाओं के औसत मूल्य को बनाया
था, जबकि मांग लागत के आधार
पर रेट तय करने की थी।